

मैसर्स पुरोलटर इंडिया लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त दिल्ली-III

(सिविल अपील No.1959/2006)

25 अगस्त, 2015

[ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: धारा 4 (2000 में यथा संशोधित) - बिक्री कर, नकद छूट, मात्रा में छूट - चाहे आंकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए कटौती योग्य- अभिनिर्धारित: नकद यहाँ तक पहुँचने के लिए छूट बिक्री मूल्य से कटौती योग्य है। माल को हटाने के समय उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य हालांकि, मात्रा छूट और बिक्री कर के बारे में, न्यायाधिकरण द्वारा मामले को सही ढंग से वापस भेज दिया गया था।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. यह देखा जा सकता है कि धारा 4 के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र, चाहे वह 1973 से पहले हो, 1973 में संशोधन के बाद हो, या 2000 के संशोधन के बाद हो, यह है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को केवल "मूल्य" का निर्धारण "हटाने के समय" करना होता है। दो संशोधनों के बाद भी धारा 4 की यह मूल विशेषता कभी नहीं बदली है। "हटाने के स्थान" में समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि इसे किसी कारखाने या निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य परिसर से गोदामों या डिपो तक विस्तारित किया जा सके, जिसमें उत्पाद शुल्क के भुगतान के साथ उत्पाद शुल्क जमा करने की अनुमति दी गई है, या जिसमें से ऐसे उत्पाद शुल्क हटाने योग्य सामान को

कारखाने से मंजूरी के बाद बेचा जाना है। वास्तव में, 2000 से पहले की धारा 4 (2) में यह स्पष्ट किया गया था कि जहां हटाने के स्थान पर डिलीवरी के लिए उत्पाद शुल्क की कीमत ज्ञात नहीं है, और उसका मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, वहां हटाने के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की लागत को ऐसी कीमत से बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धारा के तहत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य केवल हटाने के समय और स्थान पर ही निर्धारित किया जाना है। 2000 में धारा 4 के संशोधन के बाद भी यही योजना जारी है। केवल धारा 4 (2) को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। [पैरा 14) [829-बी-एफ]

2. यह देखा जा सकता है कि संशोधित धारा 4 "लेन-देन मूल्य" की अवधारणा का परिचय देती है ताकि उत्पाद शुल्क वाले माल के प्रत्येक हटाने पर, ऐसे माल का "लेन-देन मूल्य" निर्धारित किया जा सके। जबकि पहले, इस तरह के उत्पाद शुल्क का मूल्य वह मूल्य था जिस पर इस तरह के माल को आम तौर पर थोक व्यापार के दौरान बेचा जाता था, संशोधन के बाद प्रत्येक लेनदेन को स्वयं देखा जाता है। हालांकि, धारा 4 के उपखंड (3) (डी) में परिभाषित "लेन-देन मूल्य" को "हटाने के समय और स्थान पर वितरण के लिए" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जो सर्वोपरि है वह यह है कि "लेन-देन मूल्य" के आधार पर भी उत्पाद शुल्क का मूल्य केवल हटाने के समय, यानी अपीलार्थी के कारखाने या डिपो से माल की निकासी के समय, जैसा भी मामला हो, होना चाहिए। "वास्तव में भुगतान किया गया या माल के लिए देय, जब बेचा जाता है" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल यह है कि माल की कीमत के रूप में जो कुछ भी सहमत होता है वह मूल्य का आधार बनता है, चाहे "ऐसी कीमत का भुगतान किया गया हो, आंशिक रूप से भुगतान किया गया हो, या

बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया हो। "लेन-देन मूल्य" का आधार इसलिए सहमत संविदात्मक मूल्य है। इसके अलावा, "जब बेचा जाता है" अभिव्यक्ति का अर्थ उस समय को इंगित करना नहीं है जब ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं, बल्कि यह इंगित करना है कि वस्तुएं बिक्री के समझौते का विषय हैं। नकद छूट एक ऐसी चीज है जो माल की निकासी के समय या उससे पहले "ज्ञात" होती है, जो निर्धारित और उसके खरीदारों के बीच बिक्री के समझौते में निहित होती है, और इसलिए "हटाने के समय" उत्पाद शुल्क के मूल्य पर पहुंचने के लिए बिक्री मूल्य से कटौती की जानी चाहिए। [पैरा 18] [832-O-H; 833-A-B]

भारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड 1984 (17) ईएलटी 329 (एससी); भारत सरकार बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड 1995 (77) ईएलटी 433 (एससी)-पर भरोसा किया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर-॥ बनाम सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। 2014 (301) ईएलटी 273 (एससी)-विशिष्ट।

बिक्री कर उपायुक्त (विधि) राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम आडवाणी ओरलिकॉन (पी) लिमिटेड, 1981 (8) ई. एल. टी. 801 (एस. सी.)-निर्दिष्ट।

#### मामला कानून संदर्भ

1984 (17) ई. एल. टी. 329 (एस. सी.)	भरोसा किया,	पैरा 7, 15, 25
1995 (77) ई. एल. टी. 433 (एस. सी.)	भरोसा किया,	पैरा 7, 16, 25
2014 (301) ई. एल. टी. 273 (एस. सी.)	विशिष्ट,	पैरा 9, 23
1981 (8) ई. एल. टी. 801 (एस. सी.)	संदर्भित	पैरा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2006 की सिविल अपील सं. 1959

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश संख्या 1241/04-एनबी-ए दिनांक 11.11.2004 से अपील संख्या ई/1670/04-एनबी-ए।

अपीलार्थी के लिए वी. लक्ष्मीकुमारन, एम. पी. देवनाथ, विवेक शर्मा, एल. चरणया, आर. रामचंद्रन, आदित्य भट्टाचार्य, हेमंत बजाज, आनंद के., राजेश कुमार।

प्रतिवादी के लिए पिकी आनंद, ए. एस. जी., अशोक कुमार पांडा, निशा बागची, अरुणा गुप्ता, बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा दिया गया था।

1. मेसर्स पुरोलेटर इंडिया लिमिटेड (जिसे बाद में अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) उत्पाद शुल्क हटाने योग्य वस्तुओं, जैसे फ़िल्टर एलिमेंट्स, इंसर्ट और कार्ट्रिज और घटकों के निर्माण में लगा हुआ है। इन वस्तुओं को या तो अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न वाहन निर्माताओं को मंजूरी दी जाती है या स्टॉक को डिपो में स्थानांतरित किया जाता है जहां से वे आगे जाते हैं, स्टॉक को समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों को स्थानांतरित किया जाता है।

2. स्टॉक हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए, अपीलार्थी ने आबकारी विभाग के साथ नियम. 173 सी के तहत घोषणाएं दायर कीं। इन घोषणाओं में, अपीलार्थी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए देय उत्पाद शुल्क पर बिक्री कर, नकद छूट और मात्रा छूट के लिए कटौती का दावा किया।

3. विनिर्माण गतिविधियों को शुरू करने के अलावा, अपीलकर्ता कभी-कभी ग्राहकों द्वारा देखे गए दोषों के मामले में मरम्मत के लिए ग्राहकों से सामान भी प्राप्त करता है। ग्राहक या तो पूरे लॉट या एक विशेष बॉक्स आदि को अस्वीकार कर देते हैं

यदि उन्हें कोई दोष दिखाई देता है, ताकि प्रत्येक वस्तु की जाँच करने में उनका समय बर्बाद न हो और इस प्रकार, माल को अपीलार्थी को वापस भेज दिया जाए। ऐसी खेपों की प्राप्ति पर, अपीलार्थी संकेतित दोषों की जांच करता है और आवश्यक मरम्मत करता है। इसके बाद तैयार उत्पादों को ग्राहकों को वापस कर दिया जाता है। अपीलार्थी ऐसे लौटाए गए माल की प्राप्ति के लिए आवश्यक डी-3 घोषणाएँ दाखिल कर रहा था और उक्त उद्देश्यों के लिए प्रपत्र V में आवश्यक रजिस्टर का रखरखाव कर रहा था और उसके बाद नियम 173 H के प्रावधानों के तहत ऐसी मरम्मत की गई वस्तुओं को शुल्क का भुगतान किए बिना वापस कर रहा था।

4. दिनांक 02-04-2002 को एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी मात्रा में छूट, बिक्री कर और नकद छूट के कारण दावा की गई विभिन्न कटौती के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने पुराने/मरम्मत किए गए सामान के बजाय नए तैयार उत्पाद शुल्क को हटा दिया है।

5. अपीलार्थी ने प्रत्येक आरोप का प्रतिवाद करते हुए कारण दर्शाओ नोटिस का विस्तृत जवाब दाखिल किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-आई. एल. ने अप्रैल 1996 से फरवरी 1997 की अवधि के लिए सभी मुद्दों पर शुल्क मांगों को छोड़ने का एक आदेश पारित किया, जो पांच साल से अधिक पुराना था। इसके अलावा, उन्होंने जुलाई 2000 से पहले की अवधि के लिए नकद छूट के मुद्दे पर शुल्क की मांग को छोड़ दिया। हालांकि, शेष मुद्दों पर, आयुक्त ने 44,66,247-रुपये की शुल्क मांग की पुष्टि की है और 49,66,247- रुपये का अपीलार्थी पर जुर्माना भी लगाया, जो निम्नानुसार है:

#### "आदेश

ऊपर अभिलिखित चर्चा और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए-

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए (1) के पहले परंतुक में प्रदान की गई सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान करें और धारा 11 ए के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित राशियों का निर्धारण करें और निर्धारिती को तुरंत भुगतान करने का निर्देश दें।  
(ए) 13,43,046-मार्च 1997 से मार्च 2001 के बीच हटाए गए प्रतिस्थापित माल पर शामिल शुल्क के लिए।

(बी) 14,27,483-मात्रा छूट पर मार्च 1997 से मार्च, 2001 की अवधि के लिए संगणित शुल्क के लिए.

(सी) 1997 मार्च से मार्च, 2001 की अवधि के लिए बिक्री कर कटौती पर संगणित शुल्क के लिए 11,96,601 रुपये, और

(डी) 4,99,117/- रु. जुलाई 2000 से मार्च 2001 की अवधि के लिए नकद छूट पर शुल्क के लिए

(ii) इस बात की पुष्टि करता है कि धारा 11 एबी के प्रावधानों के संदर्भ में ब्याज निर्धारिती द्वारा उपरोक्त (i) (ए) से (i) (डी) की राशि पर देय है।

(iii) धारा 11 ए. सी. के प्रावधानों के तहत निर्धारिती पर 44,66,247/- रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

(iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 1730 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 के नियम 25 के प्रावधानों के संदर्भ में, सपठित धारा 38 ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, निर्धारिती पर 5 लाख रुपये का जुर्माना और

(v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 38ए के साथ पढ़ा जाता है। 29,140/- रु. 38,896/- रु. 42,728/- और रु. 19,443/- जिनका भुगतान निर्धारिती द्वारा वहन शुल्क और अंतर शुल्क के कारण स्वेच्छा से किया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त (iii) में जुर्माने की राशि को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा यदि निर्धारिती इस आदेश के संचार की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क, ब्याज और जुर्माने की राशि जमा करता है और यदि निर्धारिती पहले ही ऊपर निर्धारित बकाया के संबंध में कुछ राशि जमा/भुगतान कर चुका है, तो इस तरह के भुगतान को बकाया राशि के साथ समायोजित किया जाएगा।"

6. जब नकद छूट की बात आई, तो न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित आधार पर आयुक्त के निष्कर्ष को बरकरार रखा: -

"10. नकद छूट के संबंध में, यह विवाद में नहीं है कि नकद छूट के संबंध में शुल्क की मांग की गई है जो वास्तव में ग्राहकों को नहीं दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने पेस मार्केटिंग स्पेशलिटीज लिमिटेड, उपरोक्त के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नकद छूट माल के लिए शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट है और जब इस छूट को चालान मूल्य से कम कर दिया जाता है, तो माल की डिलीवरी के समय लेनदेन मूल्य प्राप्त किया जाता है, अन्यथा, चालान मूल्य भविष्य की कीमत है और क्योंकि मूल्यांकन योग्य मूल्य को हटाने के वित्तपोषण के समय के संबंध में निर्धारित किया जाना है और अन्य लागत आकलन योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं हो सकती है। उचित सम्मान के

साथ, हम खुद को इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की नई धारा 4 के तहत मूल्यांकन का उपाय (1.7.2000 से प्रभावी) "लेन-देन मूल्य" है न कि "मानित मूल्य" जो अधिनियम की पुरानी धारा 4 के तहत मामला था। पुरानी धारा 4 के तहत मूल्य को सामान्य मूल्य माना जाएगा, अर्थात् वह मूल्य जिस पर निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं को सामान्य रूप से किसी खरीदार को थोक व्यापार या वितरण के दौरान, हटाने के समय और स्थान पर बेचा जाता है। धारा की इस स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जेन्सन एंड निकोलसन (इंडिया) लिमिटेड के मामले में। बनाम भारत संघ, 1984 (17) ई. एल. टी. 4 (जन्म) दायर किया है कि थोक नकद मूल्य जिस पर उत्पाद शुल्क का आकलन किया जा सकता है, स्वाभाविक रूप से चालान में अनुमत नकद छूट को घटाकर मूल्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि बिक्री मूल्य के आधार पर की जाती है जिसमें स्वयं उन विभिन्न शर्तों का उल्लेख किया जाता है जिनके अधीन बिक्री की जाती है। न्यायाधिकरण ने सी. सी. ई., मेरठ बनाम स्टेशन शॉक्स लिमिटेड 1996 (85) ई. एल. टी. 139 (टी) में उक्त निर्णय का पालन किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 का प्रावधान तब से पूरी तरह से बदल गया है। नई धारा 4 के अनुसार मूल्य उस मामले में जहां निर्धारिती द्वारा माल बेचा जाता है, हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए, निर्धारिती और माल के खरीदार संबंधित नहीं हैं और बिक्री के लिए मूल्य एकमात्र विचार है, लेनदेन मूल्य होगा।" इस प्रकार वर्तमान मामले में, धारा 4



के प्रयोजन के लिए मूल्य वह लेन-देन मूल्य होगा जिसे अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा {3} के खंड (घ) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -

"संव्यवहार मूल्य" से माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य, जब बेचा जाता है, और इसमें कीमत के रूप में प्रभारित राशि के अलावा, कोई भी राशि शामिल है जो खरीदार निर्धारिती को या उसकी ओर से, बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में, चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय देय हो, जिसमें विज्ञापन या प्रचार विपणन और संगठन के खर्चों, भंडारण, बाहरी हैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी, कमीशन या किसी अन्य मामले के लिए या प्रावधान करने के लिए प्रभारित कोई राशि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि शामिल नहीं है, यदि ऐसी वस्तुओं पर वास्तव में कोई भुगतान या वास्तव में देय है।

11. "लेन-देन मूल्य" से माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य, जब बेचा जाता है, और इसमें कीमत के रूप में प्रभारित राशि के अलावा, कोई भी राशि शामिल है जो खरीदार निर्धारिती को या उसकी ओर से, बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में, चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय देय हो, जिसमें विज्ञापन या प्रचार विपणन और संगठन के खर्चों, भंडारण, बाहरी हैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी, कमीशन या किसी अन्य मामले के लिए या प्रावधान करने के लिए प्रभारित कोई राशि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों

की राशि शामिल नहीं है, यदि ऐसी वस्तुओं पर वास्तव में कोई भुगतान या वास्तव में देय है।

12. तदनुसार, हम अपील को अस्वीकार करते हैं जहां तक यह नकद छूट के कारण कटौती के भत्ते से संबंधित है। लौटाए गए माल के संबंध में मात्रा में छूट और बिक्री कर और शुल्क देयता के संबंध में, मामले को हमारे निर्देश के संदर्भ में पुनः निर्णय के लिए क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेज दिया जाता है। हम जुर्माना लगाने के मुद्दे को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ते हैं।"

7. तदनुसार, हम अपील को अस्वीकार करते हैं जहां तक यह नकद छूट के कारण कटौती के भत्ते से संबंधित है। लौटाए गए माल के संबंध में मात्रा में छूट और बिक्री कर और शुल्क देयता के संबंध में, मामले को हमारे निर्देश के संदर्भ में पुनः निर्णय के लिए क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेज दिया जाता है। हम जुर्माना लगाने के मुद्दे को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ते हैं।

8. इसके अलावा, विद्वान वकील के अनुसार, "लेन-देन मूल्य" जो पहली बार संशोधित धारा 4 में पेश किया गया था, इस तथ्य के संबंध में कोई बदलाव नहीं करता है कि ऐसा लेन-देन मूल्य केवल कारखाने या डिपो से हटाने के समय होता है, जो कारखाना परिसर या डिपो से उत्पाद शुल्क हटाने का समय होता है। उनके अनुसार, निर्धारिती द्वारा अपने खरीदारों के साथ किए गए बिक्री के प्रत्येक समझौते से माल को मंजूरी देने से पहले यह पता चलता है कि अपीलार्थी के सामान के संबंध में नकद छूट होनी चाहिए। इसलिए, यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के

कारखाने से उत्पाद शुल्क वाले माल की निकासी के समय, इस तरह की रियायती कीमत ही संशोधित धारा 4 के तहत भी अपीलार्थी के कारखाने से दिए गए माल का मूल्य होना चाहिए।

9. दूसरी ओर, विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री पिकी आनंद ने कहा है कि संशोधित धारा 4 में "लेन-देन मूल्य" की शुरुआत एक अंतर पैदा करती है और इसलिए केवल वही जो वास्तव में भुगतान किया जाता है, अपीलार्थी के माल के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए देखा जाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि जो "वास्तव में भुगतान किया गया है" वह रियायती मूल्य नहीं है, तो लेनदेन मूल्य में संभवतः नकद छूट शामिल नहीं हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर-II बनाम सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य, 2014 (301) ई. एल. टी. 273 (एस. सी.) के निर्णय पर भरोसा किया।

10. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। दोनों पक्षों के तर्कों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 4 को निर्धारित करना आवश्यक है जैसा कि उसने 1973 में किए गए संशोधन, 1973 में किए गए संशोधन और अंत में 2000 में किए गए संशोधन से पहले प्राप्त किया था।

11. 1973 में इसके संशोधन से पहले धारा 4 को इस प्रकार पढ़ा गया था:

"4. जहां इस अधिनियम के तहत कोई वस्तु वस्तु के मूल्य पर निर्भर दर पर शुल्क के साथ प्रभार्य है, वहां ऐसा मूल्य

(ए) थोक नकद मूल्य जिसके लिए समान प्रकार और गुणवत्ता की वस्तु बेची जाती है या कारखाने या निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य परिसर से शुल्क के साथ प्रभार्य वस्तु को हटाने के समय बेचा जाने में सक्षम है, या यदि निर्माण या उत्पादन का पूरा स्थान है, या

यदि ऐसी वस्तु के लिए थोक बाजार ऐसे स्थान पर, निकटतम स्थान पर मौजूद नहीं है, जहां ऐसा बाजार मौजूद है, या

(बी) जहां ऐसी कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता है, वह कीमत जिस पर समान प्रकार और गुणवत्ता की वस्तु बेची जाती है या निर्माता या निर्माता या उसके एजेंट द्वारा बेची जा सकती है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के तहत किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित करने में, व्यापार छूट और कारखाने या अन्य परिसरों से शुल्क के साथ प्रभार्य वस्तु को हटाने के समय देय शुल्क की राशि के संबंध में कोई कटौती या कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

12. 1973 के संशोधन के बाद, धारा 4 इस प्रकार है:-

"4. उत्पाद शुल्क के प्रभार के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन-(1) जहां इस अधिनियम के तहत मूल्य के संदर्भ में किसी भी उत्पाद शुल्क का प्रभार देय है, वहां ऐसा मूल्य, इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, -

(क) उसकी सामान्य कीमत, अर्थात् वह कीमत जिस पर निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं को सामान्य रूप से किसी खरीदार को थोक व्यापार के दौरान हटाने के समय और स्थान पर वितरण के लिए बेचा जाता है, जहां खरीदार कोई संबंधित व्यक्ति नहीं है और कीमत ही बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है:

बशर्ते कि-(i) जहां निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं के थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार, ऐसी वस्तुओं को विभिन्न वर्गों के खरीदारों (जो संबंधित व्यक्ति नहीं हैं) को अलग-अलग कीमतों पर बेचा जाता

है, वहां प्रत्येक ऐसी कीमत, खंड (क) में निर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों के अस्तित्व के अधीन रहते हुए, खरीदारों के प्रत्येक ऐसे वर्ग के संबंध में ऐसी वस्तुओं की सामान्य कीमत मानी जाएगी।

(क) जहां निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं को सामान्य रूप से जिस मूल्य पर बेचा जाता है, वह हटाने के विभिन्न स्थानों के लिए अलग-अलग है, वहां ऐसी प्रत्येक कीमत, खंड (क) में निर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों के अस्तित्व के अधीन रहते हुए, हटाने के प्रत्येक ऐसे स्थान के संबंध में ऐसी वस्तुओं की सामान्य कीमत मानी जाएगी।

(ii) जहां निर्धारिती द्वारा ऐसी वस्तुओं को वितरण के लिए थोक व्यापार के दौरान हटाने के समय और स्थान पर उस समय लागू किसी कानून के तहत निर्धारित मूल्य पर या किसी ऐसी कानून के तहत निर्धारित अधिकतम मूल्य पर बेचा जाता है, तो इस परंतुक के खंड (iii) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस तरह से निर्धारित मूल्य या अधिकतम मूल्य, इस तरह से बेचे गए माल के संबंध में, उसका सामान्य मूल्य माना जाएगा।

(iii) जहां निर्धारिती इस प्रकार व्यवस्था करता है कि माल आम तौर पर किसी संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से छोड़कर थोक व्यापार के दौरान उसके द्वारा नहीं बेचा जाता है, वहां निर्धारिती द्वारा ऐसे संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से बेचे गए माल की सामान्य कीमत वह कीमत मानी जाएगी जिस पर वे सामान्य रूप से संबंधित व्यक्ति द्वारा हटाने के समय थोक व्यापार के दौरान विक्रेताओं (जो संबंधित व्यक्ति नहीं हैं) को बेची जाती हैं या जहां ऐसी वस्तुएं

ऐसे विक्रेताओं को नहीं बेची जाती हैं, विक्रेताओं (जो संबंधित व्यक्ति हैं) को, जो खुदरा में ऐसी वस्तुएं बेचते हैं।

(ब) जहां ऐसी वस्तुओं की सामान्य कीमत इस कारण से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है कि ऐसी वस्तुओं को बेचा नहीं गया है या किसी अन्य कारण से, उसके निकटतम सुनिश्चित करने योग्य समतुल्य का निर्धारण ऐसी तरीके से किया जाता है जो निर्धारित की जाए।

(2) जहां किसी भी उत्पाद शुल्क के संबंध में हटाने के स्थान पर डिलीवरी के लिए उसकी कीमत ज्ञात नहीं है और उसका मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, वहां हटाने के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की लागत को ऐसी कीमत से बाहर रखा जाएगा।

(3) इस धारा के प्रावधान किसी भी उत्पाद शुल्क के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसके लिए धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत शुल्क मूल्य निर्धारित किया गया है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "निर्धारिती" का अर्थ है वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और जिसमें उसका एजेंट भी शामिल है;

(ख) "हटाने का स्थान" का अर्थ है-(i) एक कारखाना या उत्पाद शुल्क के उत्पादन या निर्माण का कोई अन्य स्थान या परिसर;

(ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जिसमें उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना उत्पाद शुल्क को जमा करने की अनुमति दी गई है;

(iii) एक डिपो, एक खेप एजेंट का परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां से उत्पाद शुल्क को उनकी मंजूरी के बाद बेचा जाना है। कारखाने से और जहाँ से इस तरह के सामान को हटाया जाता है

(ख) खंड (ख) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट हटाने के स्थान से हटाए गए माल के संबंध में "हटाने का समय", वह समय माना जाएगा जिस पर ऐसे माल को कारखाने से हटा दिया जाता है;

(ग) "संबंधित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्धारिती के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उनका एक दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है और इसमें एक होल्डिंग कंपनी, एक सहायक कंपनी, निर्धारिती का एक रिश्तेदार और वितरक और ऐसे वितरक का कोई उप वितरक शामिल है।

स्पष्टीकरण-इस खंड में "धारक कंपनी", "सहायक कंपनी" और "रिश्तेदार" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है। (घ) किसी भी उत्पाद शुल्क के संबंध में "मूल्य" -

(i) जहां सामान को पैक की गई स्थिति में हटाने के समय वितरित किया जाता है, उसमें ऐसी पैकिंग की लागत शामिल होती है, सिवाय उस पैकिंग की लागत के जो टिकाऊ प्रकृति की होती है और खरीदार द्वारा निर्धारिती को वापस की जा सकती है। स्पष्टीकरण-इस उपखंड में, "पैकिंग" का अर्थ है रैपर, कंटेनर, बॉबिन, पिरन, स्पूल, रील या वार्प

बीम या कोई अन्य चीज जिसमें या जिस पर उत्पाद से हटाने योग्य सामान को लपेटा जाता है, रखा जाता है या घाव किया जाता है।

(ii) इसमें ऐसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों, यदि कोई हो, की राशि शामिल नहीं है और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो किए जा सकते हैं, व्यापार छूट (ऐसी छूट जो किसी भी खाते में वापसी योग्य नहीं है) बिक्री के लिए बेची गई या अनुबंधित ऐसी वस्तुओं के संबंध में हटाने के समय थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार अनुमत है।

स्पष्टीकरण-इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी भी उत्पाद शुल्क की राशि का कुल योग होगा-(ए) इस अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का प्रभावी योग। और (ख) अन्य केंद्रीय अधिनियमों, यदि कोई हों, के तहत देय उत्पाद शुल्क के प्रभावी शुल्कों का कुल, जो ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है, और खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का प्रभावी होना इस प्रकार होगा-

(i) ऐसे मामले में जहां किसी अधिसूचना या आदेश में ऐसी वस्तुओं के संबंध में छूट (जो ऐसी अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के संबंध में छूट या कटौती नहीं है, जो ऐसे अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के बराबर है, या सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत अतिरिक्त शुल्क, जो पहले से ही कच्चे माल या ऐसे सामान के उत्पादन या निर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटक



भागों पर भुगतान किया जा चुका है) को ऐसे अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क से कुछ समय के लिए लागू किया गया है, ऐसे अधिनियम में निर्दिष्ट दर के संदर्भ में संगणित उत्पाद शुल्क, जो कम किया गया है। और

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसे माल के संबंध में ऐसे अधिनियम में निर्दिष्ट दर के संदर्भ में संगणित उत्पाद शुल्क.

(ड) "थोक व्यापार" का अर्थ है विक्रेताओं, औद्योगिक उपभोक्ताओं, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य खरीदारों को बिक्री, जो खुदरा के अलावा अपनी आवश्यकताओं को खरीदते हैं या खरीदते हैं।"

13. धारा 4, जैसा कि 2000 के संशोधन के बाद पढ़ा जाता है, इस प्रकार है:-

"4. उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन-(1) जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी उत्पाद शुल्क का प्रभार किसी भी उत्पाद शुल्क के मूल्य के संदर्भ में लगाया जाता है, तो माल के प्रत्येक हटाने पर, ऐसा मूल्य होगा-

(ए) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती द्वारा माल बेचा जाता है, हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए, निर्धारिती और माल का खरीदार संबंधित नहीं हैं और बिक्री के लिए मूल्य एकमात्र प्रतिफल है, लेनदेन मूल्य होगा;

(बी) किसी अन्य मामले में, जिसमें माल बेचा नहीं जाता है, उस तरीके से निर्धारित मूल्य होगा जो निर्धारित किया जा सके।

(2) इस धारा के प्रावधान किसी भी उत्पाद शुल्क के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसके लिए धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत शुल्क मूल्य निर्धारित किया गया है।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए,-(क) "निर्धारिती" का अर्थ है वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है; (ख) व्यक्तियों को "संबंधित" माना जाएगा यदि-

(i) वे आपस में जुड़े उपक्रम हैं;

(ii) वे रिश्तेदार हैं;

(iii) उनमें से खरीदार निर्धारिती का रिश्तेदार और वितरक या ऐसे वितरक का उप-वितरक होता है। या

(iv) वे इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के व्यवसाय में रुचि रखते हैं।

स्पष्टीकरण।-इस खंड में -

(i) "आपस में जुड़े उपक्रमों" का वही अर्थ होगा जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 64) की धारा 2 के खंड (छ) में दिया गया है; और (ii) "रिश्तेदार" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (41) में दिया गया है; (ग) "हटाने का स्थान" का अर्थ है-(i) एक कारखाना या उत्पाद शुल्क का उत्पादन या निर्माण का कोई अन्य स्थान या परिसर;

(ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां से उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी गई है, जहां से ऐसी वस्तुओं को हटाया गया है।

(d) ""लेन-देन मूल्य" से माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य, जब बेचा जाता है, अभिप्रेत है और इसमें मूल्य के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि शामिल है, जिसे खरीदार निर्धारिती की ओर से या उसकी ओर से, बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में, चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय देय हो, जिसमें विज्ञापन या प्रचार, विपणन और बिक्री, संगठन के खर्च, भंडारण, बाहरी संचालन, सेवा, वारंटी, कमीशन या किसी अन्य मामले के लिए प्रभारित या प्रावधान करने के लिए प्रभारित कोई राशि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, वास्तव में भुगतान या वास्तव में देय, शामिल नहीं है।"

14. यह देखा जा सकता है कि धारा 4 के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र, चाहे वह 1973 से पहले हो, 1973 में संशोधन के बाद हो, या 2000 के संशोधन के बाद हो, यह है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को केवल "मूल्य" का निर्धारण "हटाने के समय" करना होता है। दो संशोधनों के बाद भी धारा 4 की यह मूल विशेषता कभी नहीं बदली है। "हटाने के स्थान" में समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि इसे किसी कारखाने या निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य परिसर से गोदामों या डिपो तक विस्तारित किया जा सके, जिसमें उत्पाद शुल्क के भुगतान के साथ उत्पाद शुल्क जमा करने की अनुमति दी गई है, या जिसमें से ऐसे उत्पाद शुल्क हटाने योग्य सामान को कारखाने से मंजूरी के बाद बेचा जाना है। वास्तव में, 2000 से पहले की धारा 4 (2)

में यह स्पष्ट किया गया था कि जहां हटाने के स्थान पर डिलीवरी के लिए उत्पाद शुल्क की कीमत ज्ञात नहीं है, और उसका मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, वहां हटाने के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की लागत को ऐसी कीमत से बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धारा के तहत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य केवल हटाने के समय और स्थान पर ही निर्धारित किया जाना है। 2000 में धारा 4 के संशोधन के बाद भी यही योजना जारी है। केवल धारा 4 (2) को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

15. 1973 के बाद, इस न्यायालय ने अपने दो निर्णयों में, अर्थात् भारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड, 1984 (17) ई. एल. टी. 329 (एस. सी.) में, स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

"व्यापार छूट-व्यापार में अनुमत छूट (चाहे किसी भी नाम से ऐसी छूट का वर्णन किया गया हो) को माल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बिक्री मूल्य से काटने की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि समझौतों के तहत या बिक्री की शर्तों के तहत या स्थापित प्रथा द्वारा स्थापित किया गया है, तो छूट की प्रकृति और प्रकृति जो माल को हटाने के समय या उससे पहले ज्ञात है। इस तरह की व्यापार छूट की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि वे प्रत्येक चालान के समय देय नहीं हैं या चालान मूल्य से कटौती नहीं की गई है।"

16. भारत सरकार बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड, 1995 (77) ई. एल. टी. 433 (एस. सी.) के दूसरे निर्णय में जो अभिनिर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है:-

"ईयर एंडिंग डिस्काउंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट: जिसे 'ईयर एंडिंग डिस्काउंट' कहा जाता है, वह वास्तव में मद्रास रबर फैक्ट्री द्वारा अपने डीलरों को एक विशेष प्रकार के टायरों के संबंध में प्रति टायर पचास रुपये का बोनस है। यह छूट केवल तभी देय है जब भुगतान वास्तव में चालान की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्राप्त किया जाता है। इस योजना के तहत, ऐसा प्रतीत होता है कि एक घोषणा विक्रेता-वार प्राप्त की जानी है और उसके बाद बोनस के लिए एम. आर. एफ. के मुख्य कार्यालय में प्रावधान किया जाना है। सहायक कलेक्टर ने पाया है कि इस छूट की अनुमति निर्धारिती द्वारा किसी भी अतिरिक्त-वाणिज्यिक विचार के कारण नहीं दी गई थी, बल्कि वे केवल उस वर्ष के लिए बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लीडर टायर के संबंध में वर्ष 1981-82 में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए थी। उन्होंने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि "छूट देने की ऐसी प्रणाली सामान्य व्यापार व्यवहार में प्रचलित है और अंतर केवल यह हो सकता है कि एम. आर. एफ. लिमिटेड ने केवल वर्ष के अंत में छूट दी है न कि वास्तविक बिक्री के समय।" विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उस आधार की शुद्धता पर विवाद किया जिसके आधार पर सहायक कलेक्टर ने इस कटौती की अनुमति दी है। उन्होंने 20 दिसंबर, 1986 के फैसले के पैरा 13 (ii) (केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री) में तर्क को स्वीकार करने के लिए हमारी सराहना की। उक्त क्रम में तर्क इस प्रकार है:

"छूट का भत्ता माल को हटाने के समय या उससे पहले ज्ञात नहीं है। गणना वर्ष के अंत में की जाती है और उक्त दर पर बोनस

केवल विक्रेताओं के एक विशेष वर्ग को दिया जाता है। एम. आर. एफ. और उसके विक्रेताओं के बीच खातों का जायजा लेने के बाद इसकी गणना की जाती है। यह छूट की प्रकृति में नहीं है, बल्कि बोनस या प्रोत्साहन की प्रकृति में है, जब चालान उठाया जाता है और माल को हटाना पूरा हो जाता है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि एम. आर. एफ. इस शीर्ष के तहत कटौती का हकदार नहीं है।

हालाँकि, हमारी यह सम्मानजनक राय है कि सहायक कलेक्टर द्वारा दर्ज किए गए स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुए उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि छूट की यह प्रणाली उद्योग में प्रचलित है और विशेष वस्तुओं को हटाने के समय जानी और समझी जाती है, हालाँकि राशि की मात्रा बाद में निर्धारित की जाती है। उक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए और बॉम्बे टायर इंटरनेशनल में स्पष्टीकरण आदेश के आलोक में, हम मानते हैं कि सहायक कलेक्टर द्वारा इस दावे की अनुमति दी गई है।

जहाँ तक शीघ्र भुगतान छूट का संबंध है, यह 'शीघ्र भुगतान छूट योजना' नामक एक योजना के तहत देय है जो केवल अप-कंट्री गैर-आर. सी. एस. विक्रेताओं (निश्चित रूप से, सरकार और डी. जी. एस. और डी. खातों को छोड़कर) पर लागू होती है। बिक्री कर, अधिभार आदि सहित चालान के कुल मूल्य पर छूट 0.75% है बशर्ते बिल चालान की तारीख से 26 दिनों के भीतर साफ़/भुगतान किया जाए। भारत संघ का मामला यह है कि यह छूट केवल कुछ प्रकार के उत्पादों तक ही सीमित है जैसा कि योजना दस्तावेज में बताया गया है और यह केवल एक सीमित अवधि के लिए मान्य है। हालाँकि,

सहायक कलेक्टर ने इस छूट को वर्ष समाप्ति छूट के साथ निपटाया और इसे उसी तर्क पर अनुमति दी जो वर्ष समाप्ति छूट पर लागू होती है।

सहायक कलेक्टर द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और बॉम्बे टायर इंटरनेशनल में स्पष्टीकरणात्मक आदेश को देखते हुए यह भी माना जाना चाहिए कि इस दावे को सहायक कलेक्टर द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी।"

17. हमारे निर्धारण के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या वर्ष 2000 में संशोधित धारा 4 उपरोक्त स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती है।

18. यह देखा जा सकता है कि संशोधित धारा 4 "लेन-देन मूल्य" की अवधारणा का परिचय देती है ताकि उत्पाद शुल्क वाले माल के प्रत्येक हटाने पर, ऐसे माल का "लेन-देन मूल्य" निर्धारित किया जा सके। जबकि पहले, इस तरह की उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं का मूल्य वह मूल्य था जिस पर इस तरह की वस्तुओं को आम तौर पर थोक व्यापार के दौरान बेचा जाता था, संशोधन के बाद प्रत्येक लेनदेन को स्वयं देखा जाता है। हालांकि, धारा 4 के उपखंड (3) (डी) में परिभाषित "लेन-देन मूल्य" को "हटाने के समय और स्थान पर वितरण के लिए" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जो सर्वोपरि है वह यह है कि "लेन-देन मूल्य" के आधार पर भी उत्पाद शुल्क का मूल्य केवल हटाने के समय, यानी अपीलार्थी के कारखाने या डिपो से माल की निकासी के समय, जैसा भी मामला हो, होना चाहिए। "वास्तव में भुगतान किया गया या माल के लिए देय, जब बेचा जाता है" अभिव्यक्ति का केवल यह अर्थ है कि माल की कीमत के रूप में जो कुछ भी सहमत होता है, वह मूल्य का आधार है, चाहे वह कीमत का भुगतान किया गया हो, आंशिक रूप से

भुगतान किया गया हो, या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया हो। "लेन-देन मूल्य" का आधार इसलिए सहमत संविदात्मक मूल्य है। इसके अलावा, "जब बेचा जाता है" अभिव्यक्ति का अर्थ उस समय को इंगित करना नहीं है जब ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं, बल्कि यह इंगित करना है कि वस्तुएं बिक्री के समझौते का विषय हैं।

एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो निर्धारिती के विद्वान वकील ने जो तर्क दिया है, उसे अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि नकद छूट एक ऐसी चीज है जो माल की निकासी के समय या उससे पहले "ज्ञात" है, जो निर्धारिती और उसके खरीदारों के बीच बिक्री के समझौते में निहित है, और इसलिए "हटाने के समय" उत्पाद शुल्क के मूल्य पर पहुंचने के लिए बिक्री मूल्य से कटौती की जानी चाहिए।

19. हमें जनवरी-मार्च, 1975 की अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के बुलेटिन में भेजा गया था जिसमें बोर्ड ने कहा था:- "नकद छूट यानी डिलीवरी पर माल की कीमत के त्वरित भुगतान के लिए छूट, सभी खरीदारों के लिए उपलब्ध होने पर आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने में स्वीकार्य हैं। इस पहलू पर "मूल्य" शीर्षक के तहत विस्तार से चर्चा की गई है।

" ... कुछ निर्धारिती अपने सभी खरीदारों को नकद छूट दे सकते हैं, जो कि शीघ्र भुगतान के लिए छूट है। दूसरे शब्दों में, वे नकद भुगतान होने पर कुछ कम कीमत लेते हैं, लेकिन यदि भुगतान नकद में नहीं किया जाता है तो अधिक कीमत (यानी नकद छूट की कटौती के बिना) लेते हैं। ऐसे मामलों में, नकद छूट, यदि अनुमति दी जाती है, तो इस सिद्धांत पर स्वीकार्य होगी कि नकद छूट की कटौती के बाद प्राप्त शुद्ध मूल्य ही माल की कीमत है।



चित्र. (iv) निर्धारिती ए सामान को रुपये में बेचता है। 100 प्रति यूनिट लेकिन 2 प्रतिशत की नकद छूट दी जाती है यदि भुगतान डिलीवरी के समय या एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाता है। इस तरह की नकद छूट स्वीकार्य होगी और कीमत रु. 100 प्रति इकाई माइनस 2 प्रतिशत।"

20. बोर्ड की यह समझ आवश्यक रूप से वर्ष 2000 में धारा 4 के संशोधन के बाद भी नकद छूट के संबंध में ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए जारी रहेगी।

21. हमें बिक्री कर उपायुक्त (विधि) राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम आडवाणी ओरलिकॉन (पी) लिमिटेड, 1981 (8) ई. एल. टी. 801 (एस. सी.) मामले में इस न्यायालय के फैसले के लिए भेजा गया था, जिसमें कहा गया था: -

" ... नकद छूट की अनुमति तब दी जाती है जब खरीदार तुरंत या स्वीकृत क्रेडिट अवधि के भीतर भुगतान करता है। यह एक छूट है जो शीघ्र भुगतान के विचार में दी जाती है। व्यापार छूट थोक विक्रेताओं द्वारा व्यापार में लगे खुदरा विक्रेताओं को दी जाने वाली वस्तुओं की सूची मूल्य से कटौती है। भत्ता खुदरा विक्रेता को सूची मूल्य पर माल बेचने में सक्षम बनाता है और फिर भी अपने व्यावसायिक खर्च को ध्यान में रखते हुए उचित लाभ अर्जित करता है। एक थोक विक्रेता द्वारा एक खुदरा विक्रेता को भेजा गया बाहरी चालान सूची मूल्य दिखाता है और उसके खिलाफ व्यापार छूट की कटौती दिखाई जाती है। शुद्ध राशि बिक्री मूल्य है, और यह वह शुद्ध राशि है जो संबंधित

पक्षों की पुस्तकों में प्राप्य राशि के रूप में दर्ज की जाती है। (पैरा 5 पर)

22. यह निर्णय केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के संदर्भ में आया है, लेकिन यह केवल इस मायने में शिक्षाप्रद है कि यह स्पष्ट करता है कि नकद छूट शीघ्र भुगतान के विचार में दी गई छूट है और इसलिए इसका सीधे तौर पर मूल्य से संबंध है।

23. केवल राजस्व के मामले, अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर-॥ बनाम सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर चर्चा करना बाकी है। उक्त निर्णय राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत दिए गए बिक्री कर प्रोत्साहनों से संबंधित था। उस मामले के तथ्यों पर, बिक्री कर का 25 प्रतिशत सरकार को भुगतान किया गया था, और बिक्री कर की उक्त राशि का 75 प्रतिशत निर्धारिती द्वारा बरकरार रखा गया था और निर्धारिती का लाभ बन गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए बोर्ड के पहले के परिपत्रों के तहत, बिक्री कर की 75 प्रतिशत राशि जो कभी भी सरकार को भुगतान नहीं की गई थी, लेकिन निर्धारिती द्वारा बरकरार रखी गई थी, वह भी पुरानी धारा 4 के तहत "मूल्य" से कटौती के लिए उत्तरदायी थी, यानी वर्ष 2000 में इसके संशोधन से पहले की धारा 4, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधित धारा 4 की आवश्यकता होगी कि 75 प्रतिशत की ऐसी राशि बिक्री कर के रूप में कटौती योग्य नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के अनुसार, केवल बिक्री कर जो "वास्तव में भुगतान किया गया है" 2000 में संशोधित धारा 4 के बाद काटा जा सकता है। इस अदालत ने कहा: -

"उपरोक्त परिपत्र में प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत "लेन-देन मूल्य" पर पहुंचने के लिए अनुमेय बिक्री

कर की राशि की गणना करने के लिए सेट ऑफ को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि सेट ऑफ देय/प्रभार्य बिक्री कर की दर को नहीं बदलता है, लेकिन वास्तव में इनपुट पर भुगतान किए गए बिक्री कर के सेट ऑफ के कारण कम राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, यदि निवेश पर बिक्री कर का भुगतान नहीं किया गया था, तो पूरी राशि देय है और "लेनदेन मूल्य" पर पहुंचने के लिए इसे बाहर रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स नहीं है। वर्तमान मामले में निर्धारिती ने केवल 25 प्रतिशत का भुगतान किया है और बिक्री कर के रूप में एकत्र की गई राशि का 75 प्रतिशत अपने पास रखा है। एकत्र की गई राशि का 75 प्रतिशत बरकरार रखा गया और यह लाभ या खरीदार द्वारा निर्धारिती को भुगतान की गई प्रभावी लागत बन गई। बिक्री कर के रूप में देय राशि सामान्य बिक्री कर का केवल 25 प्रतिशत थी। उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में "लेन-देन मूल्य" या मूल्य को परिभाषित करने का उद्देश्य और उद्देश्य स्पष्ट है। निर्माता को भुगतान की गई कीमत या लागत वह आकलन योग्य मूल्य है जिस पर उत्पाद शुल्क देय है। यह भी स्पष्ट है कि उत्पाद शुल्क लगाने के लिए लेन-देन मूल्य की गणना करते समय देय उत्पाद शुल्क को बाहर रखा जाना चाहिए। बिक्री कर या वैट या कारोबार कर राज्य सरकार को लेन-देन पर देय या भुगतान किया जाता है, जिसे बिक्री माना जाता है, यानी विनिर्मित वस्तुओं में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए। बिक्री कर, वैट आदि के लिए राज्य सरकार को भुगतान या देय राशि को बाहर रखा गया है क्योंकि यह कीमत के लिए निर्माता को भुगतान की गई राशि नहीं है, बल्कि

बिक्री लेनदेन के लिए राज्य सरकार को भुगतान या देय राशि है, यानी निर्माता से किसी तीसरे पक्ष को स्वामित्व का हस्तांतरण। तदनुसार, राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि केवल लेन-देन मूल्य से बाहर है। जो देय नहीं है या बिक्री कर/वैट के रूप में भुगतान किया जाना है, उससे तीसरे पक्ष/ग्राहक से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन यदि यह लिया जाता है और देय या भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह एक हिस्सा है और इसे लेनदेन मूल्य से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। संशोधन के बाद यह स्थिति है, क्योंकि संशोधित प्रावधान के अनुसार "लेन-देन मूल्य" शब्दों का अर्थ है वास्तविक आधार पर किया गया भुगतान या वास्तव में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया। जो शब्द अर्थ प्राप्त करते हैं वे "वास्तव में भुगतान किए गए" होते हैं। 1 के बाद की स्थिति। 7000 एक ऐसी स्थिति को शामिल नहीं करता है जिसे परिपत्र दिनांक 12.3.1998 के तहत शामिल किया गया था। जो भी हो, स्पष्ट विधायी इरादा, जैसा कि हमें लगता है, "वास्तव में भुगतान" पर है। इस मामले में "वास्तव में देय" का सवाल नहीं उठता है। "(पैरा 22 पर)

24. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय ने वर्ष 2000 में संशोधित धारा 4 (1) (ए) पर विचार नहीं किया क्योंकि यह हटाने के समय और स्थान पर माल की डिलीवरी की बात करता है। यह न्यायालय केवल इस बात से संबंधित था कि क्या बिक्री कर को "लेन-देन मूल्य" से काटा जाना है जैसा कि नए परिभाषित किया गया है। हम पहले ही देख चुके हैं कि "लेन-देन मूल्य" विशेष रूप से बताता है कि इसमें "वास्तव में भुगतान किया गया या वास्तव में ऐसी वस्तुओं पर देय" बिक्री कर शामिल नहीं होगा। उस मामले के तथ्यों पर, यह न्यायालय "वास्तव में देय" अभिव्यक्ति से

संबंधित नहीं था क्योंकि यह उस मामले में उत्पन्न नहीं हुआ था। यह न्यायालय केवल बिक्री कर से संबंधित था जो राजस्थान सरकार को "वास्तव में भुगतान" नहीं किया गया था, और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बिक्री कर का 75 प्रतिशत निर्धारिती द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए उक्त राशि की कटौती केवल राज्य सरकार को देय राशि के रूप में नहीं की जा सकती क्योंकि बिक्री कर की कटौती की जा सकती है। यह "लेन-देन मूल्य" की परिभाषा के अंतिम भाग की व्याख्या पर आयोजित किया गया था। वर्तमान मामले के तथ्य "लेन-देन मूल्य" की परिभाषा के पहले भाग से संबंधित हैं जिसे धारा 4 (1) (ए) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि ऊपर कहा गया है।

25. जहां तक नकद छूट का संबंध है, यह निर्णय किसी भी तरह से तय की गई कानूनी स्थिति से विचलित नहीं होता है जैसा कि भारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल (ऊपर) और भारत सरकार बनाम एम. आर. एफ. (ऊपर) में निर्धारित किया गया है। वास्तव में, जैसा कि पहले बताया गया है, यह निर्णय खुद को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की "कीमत" से संबंधित नहीं था, जिसे केवल कारखाने के द्वार से हटाने के समय ही निर्धारित किया जाना चाहिए। चूंकि यह न्यायालय केवल इस बात से संबंधित था कि बिक्री कर के रूप में कुछ राशियों को "मूल्य" से काटा जाना था या नहीं, इसलिए उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर बहुत कम लागू होता है।

26. ऊपर जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि 2000 में संशोधित धारा 4 के तहत भी "कीमत" पर पहुंचने में "नकद छूट" को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

27. जहां तक दोषपूर्ण वस्तुओं और बिक्री कर पर मात्रा में छूट के अन्य बिंदु का संबंध है, न्यायाधिकरण ने कहा है:

"8. हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है। दोषपूर्ण वस्तुओं के संबंध में, हम श्री आर. के. गुलाटी के दिनांकित 9.10.2000 के बयान से देखते हैं कि उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि "उक्त के तहत विभिन्न ग्राहकों से इस तरह से प्राप्त माल। डी 3 को वास्तव में ठीक नहीं किया गया है और पूरे नए तैयार उत्पादों को खरीदार को भेज दिया गया है क्योंकि इसे माल के रूप में ठीक किया गया है। उत्पाद शुल्क मामलों के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ओर से यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि वापस प्राप्त दोषपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर नए उत्पाद शुल्क को हटा दिया गया था। श्री गुलाटी ने इस कथन को बिल्कुल भी वापस नहीं लिया है। चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र दिनांकित 5.7.2002 है जो हमारे सामने वर्तमान मामले में शामिल अवधि के बहुत बाद है और अपीलकर्ता कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्पष्ट स्वीकारोक्ति को दूर नहीं कर सकता है। हम इस निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं कि श्री गुलाटी के बयान पर केवल खंडसा कारखाने के संबंध में भरोसा किया जा सकता है न कि महारौली रोड पर कारखाने के संबंध में क्योंकि श्री गुलाटी ने अपने बयान में ऐसी कोई योग्यता संलग्न नहीं की है। इसके अलावा, यदि दोषपूर्ण वस्तुओं को एक कारखाने में नए सामान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो यह शामिल करना उचित होगा कि वही प्रथा उसी निर्माता के दूसरे कारखाने में प्रचलित होगी। इसलिए हमारा मानना है कि अपीलकर्ता अपने ग्राहकों को वापस प्राप्त दोषपूर्ण सामान के बदले में नए उत्पाद शुल्क को हटा रहे थे। हालाँकि, हम विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल पाते हैं कि दोषपूर्ण वस्तुओं के संबंध में शुल्क की

मांग नहीं की जा सकती है, जिनके खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी उत्पाद शुल्क को मंजूरी नहीं दी गई थी। इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने के भीतर अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री/साक्ष्य पर पुनर्विचार करने के लिए इस पहलू को क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजा जा रहा है।

9. मात्रा में छूट और बिक्री कर के संबंध में, विवाद उनकी कटौती के संबंध में नहीं है, बल्कि मात्रा में छूट की वास्तविक राशि या भुगतान किए गए बिक्री कर के संबंध में है। हमारे विचार में माल के आकलन योग्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से अपीलार्थी द्वारा दी गई छूट की वास्तविक राशि और भुगतान/देय बिक्री कर की वास्तविक राशि में कटौती की जानी चाहिए। यह एक तथ्यात्मक मामला है-- जिसे इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने के भीतर अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा फिर से देखा जाना चाहिए।"

28. दोनों पक्षों ने हमसे अनुरोध किया है कि चूंकि इन मुद्दों पर न्यायाधिकरण के आदेश के संदर्भ में मामले को रिमांड पर लिया जा रहा है, इसलिए रिमांड एक ओपन-एंडेड होनी चाहिए, अर्थात्, दोनों पक्षों को उन सभी बिंदुओं पर नए सिरे से बहस करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो इन मुद्दों के संबंध में उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम न्यायाधिकरण के रिमांड के आदेश की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों को उन सभी बिंदुओं पर बहस करने की अनुमति देते हैं जो इन मुद्दों के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। जहाँ तक नकद छूट के मुद्दे का संबंध है, हम न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हैं।

29. अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है।

देविका गुजराल

अपील का निपटारा किया जाता है।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।